who have given tins proposal. If not, what is the reason fur allowing this coat-pased plant again, when there is another prant in Gujarat aireaay ready for commissioning, out for Want of coat is not being commissioned?

SHRI N. K. P. SALVE; Sir, im. ported coal, so far, was expensive pecause of the import duty. Now that the import duty has been lessened, reduced very .subsatntially, should they have to import coal (the import of coal bieng under Q.G..L.)—they can import and get it.

SHRI ASHOK MITRA; Mr. Chairman, Sir, coming from a State which produces coal and worried about the problem of unemployment among the coal miners, I would like to know from the hon.' Minister whether he has taken note of the fact that we have a telescopic structure in regard to haulage of coal; the longer the distance the lowe. is the unit cost of transportation. For example, coal from Raniganj would cost higher to be transported to Durgapur than it would cost to transport it to Gujarat. In view of this and in view also of the fact that there lis a social cost involved in having unemployed miners in our society I would like to know whether the Government would be prepared to review the entire system of import of coal for power plants.

SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU: Mr. Chairman, Sir, I would like to submit that this supplementary does not arise out of the main question.

SHRI ASHOK MITRA: Why should it not?

SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU: The question is about the Gujarat projects which are based on lignite.

SHRI ASHOK MITRA: Coal-based projects.

MR. CHAIRMAN: Dr. Naunihai Singh. (Interruptions)

SHRI ASHOK MITRA; If the Minister does not want to answer, let nun say that he does not want to answer; the has not prepared. But m-3 is very very relevant.

MR. CHAIRMAIN; This is a little out of it.

SHRI N. K. P. SALVE; Sir, there is no question ox not answering let him put a specific question. We are ready to answer it not once but one hundred times. We are ready to answer. Please do not make imputations. I refute the imputations completely. (Interruptions) Let a relevant question be asked. Put a specific question. You give notice. I strongly protest, Sir. *(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN; I have already called the next person, please. Dr. Naunihai Singh.

DR. NAUNIHAL SINGH; I would like to ask the hon. Minister whether the 16 per cent return on investment in the power sector available to foreign firms is available to the Indian firms also. If not, why not? Secondly, would the State Electricity Boards open Letters of Credit in favour of foreign parties to ensure payments to them for the power supplied? If so, to how many cases have Letters of Credit been opened so far?

SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU: Sir, the 16 per cent return on investment is applicable only to the private companies and not to the public sector projects.

दिल्ली में बिजली की मांग

***226. श्री राम जेठमलानी :**
डा. विनेन्द्र कुमार जैन : †

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली राज्य में बिजली की औसत मांग लगभग 1400 मेगावाट है ;

†सभा में यह प्रश्न डा० विनोद कुमार जैन द्वारा पूछा गया ।

(ख) क्या यह भी सच है कि बिजली की उक्त मांग के 1997 तक 2500 मेगावाट तक हो जाने का अनुमान है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि दिल्ली में दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा केवल 550 मेगावाट बिजली का ही उत्पादन किया जा रहा है ;

(घ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में तथ्य क्या हैं ;

(ङ) क्या यह भी सच है कि वर्तमान विद्युत उत्पादन, वितरण तथा पारगमन व्यवस्था में व्यापक सुधार लाने के सम्बन्ध में सरकार को भी विभिन्न स्रोतों से सुझाव प्राप्त हुए हैं ;

(च) यदि हां, तो फरवरी, 1994 तक सरकार को किस-किस प्रकार के सुधार के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और उनका ब्यौरा क्या है ; और

(छ) उन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है, जिन्हें सरकार ने कार्यान्वित करने का निर्णय ले लिया है ?

विद्युत मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) से (छ) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

(क) से (घ) दिल्ली में प्रतिदिन बिजली की औसत खपत लगभग 31 मिलियन यूनिट है। दिल्ली में इस समय व्यस्ततमकालीन भार सम्बन्धी मांग लगभग 1600 मेगावाट है जोकि वर्ष 1997 तक बढ़कर 2532 मेगावाट हो जाने की संभावना है । 599.5 मेगावाट की अधिष्ठापित क्षमता की अपेक्षा डेसू द्वारा उत्पादित विद्युत की मात्रा वस्तुतः लगभग 350 मेगावाट है ।

(ङ) से (छ) वर्ष 2005 तक की प्रत्याशित भार सम्बन्धी मांग को पूरा करने हेतु दिल्ली में पारेषण एवं वितरण प्रणाली के लिए मास्टर योजना तैयार करने का कार्य, डेसू द्वारा परामर्शदाताओं के रूप में मैसर्स स्वीडपावर (एक स्वीडिश एजेन्सी) की सेवाएं प्राप्त की जा रही हैं। इस एजेन्सी को सौंपा गया है । मैसर्स स्वीडपावर द्वारा की गई सिफारिशें, विभिन्न वोल्टता स्तरों पर पारेषण एवं वितरण कार्य का विस्तार करने/इसे सशक्त बनाने, उपकेन्द्रों/वितरण नेटवर्क के लिए विद्युत सप्लाई की गुणवत्ता हेतु डिजाइन में सुधार करने वस्तुतः समय मूल्यों के आधार पर पारेषण एवं वितरण प्रणाली का मानीटरिंग और प्रचालन कार्य करने के लिए आधुनिक और कम्प्यूटरीकृत पर्यवेक्षी नियंत्रण और आंकड़े प्रापण प्रणाली (एस० सी० ए० डी० ए०) अधिष्ठापित करने से संबंधित हैं । डेसू ने मैसर्स स्वीड-पावर की सिफारिशों का क्रियान्वयन किए जाने के लिए कार्यवाही की शुरूआत कर दी है। विद्युत सप्लाई की विश्वसनीयता एवं गुणवत्ता में सुधार किये जाने के लिए दिल्ली में पुराने शहरी इलाके की समय वितरण प्रणाली का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। निवेश सम्बन्धी निर्णय लिए जाने के लिए एस०सी०ए०डी०ए० प्रणाली के बारे में एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है । दिल्ली के चारों ओर एक 400 के०वी० पारेषण प्रणाली का निर्माण किया जाना भी विचाराधीन है ।

सरकार द्वारा गठित कृतिक बल ने उपभोक्ताओं हेतु बेहतर प्रबन्ध और दक्ष सेवा उपलब्ध कराये जाने के लिए दिल्ली में विद्युत वितरण का निजीकरण करने की सिफारिश की है । दिल्ली में विद्युत वितरण का निजीकरण किए जाने के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा पहले ही प्रस्ताव आमंत्रित किये गये हैं । बवाना में 450 मे०वा० की गैस आधारित विद्युत परियोजना निजी क्षेत्र में अधिष्ठापित किए जाने की परिकल्पना की गई है । दिल्ली में विद्युत सप्लाई प्रणाली के प्रबन्ध हेतु एक उपयुक्त तथा दक्ष प्रणाली उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली में एक बिजली बोर्ड का गठन किए जाने से संबंधित प्रस्ताव पर भी सरकार द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ।

DR. JINENDRA KUMAR JAIN: Sir. the Minister's answer is more

disappointing than what I had presumed. I say this because, according to the answer while Delhi's power need is 1600 MW—this would go up to 2532 MW—the present producttoa is only 350 MW as against the installed capacity of 599 MW. In view of this, I would like to know from the hon. Minister as to what is the plan of the Government? Do they have a plan to make Delhi self-sufficient in terms of its power needs? If they have a plan, within what timeframe do they intend to achieve the target so as to make Delhi self-sufficient in terms of its power needs?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): Sir, the following measures are beling taken to meet the future requirements for power in Delhi.

A 400/450 MW gas-based power plant is proposed to be established at Bawana, in the private sector. Offers received from private par. ties have been evaluated by the CEA and DESU lis taking action to select a suitable offer. Then, 3x 34.07 MW waste heat recovery units are also under installation at the gas turbines. D.E.S.U. has been allowed 90 per cent share in the Dadri Thermal Power Plant. Two units Of 210 MW each are already on commercial production. A 400 KV transmission ring is being constructed to bring bulk power from the central stations in the Northern Region D.E.S.U. will also benefit from the Central power projects coming up in the Northern Region, i.e. Chamera Hydro, Salal Stage II, Dadri Thermal, Dadri Gas Turbine and Unchahar.

"DR."JINENDRA KUMAR JAIN: Is there a proposal 'from the Delhi Gavernment to provide electricity connections to all *jhuggis/jhonpris?* If there is a proposal, hag the Government of India agreed to such a proposal? What would be the additional burden of such a decision and how does the Government propose to make electricity available to Delhi in ease this decision is implemented during the peak hours?

SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU: Sir, the decision to supply power to ihuggis /*jhonpris* is entirely of the State Government and DESU. It is not for the Government of India to decide about this issue because, basically, distribution is entirely in the hands of DESU, and no reference has been made by the Delhi Government in this regard. Naturally if all the *jhuggis jhopris* are provided power connections, there will be an excess demand, and that can be calculated from the number of applications received and the total power required. ...(Interruptions)...

प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा : सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि दिल्ली में हर गर्मियों में कई-कई दिन बिजली नहीं आती, कई-कई दिन तक लोगों को परेशान रहना पड़ता है। खेती के लिए बिजली नहीं मिलती है, इंडस्ट्री के लिए बिजली नहीं मिलती है और 15-15 दिन, 10-10 दिन तक इंडस्ट्रियल एरिया में बिजली नहीं आती है। इतनी खराब हालत बिजली की जो दिल्ली में है, उसको ठीक करने के लिए ये जितनी योजनाएं बताई हैं, ये सारी कागजों में हैं या इन गर्मियों में स्थिति ठीक हो जाएगी?

श्री अजीत जोगी : क्या आप दिल्ली की सरकार को गिरवाना चाहते हैं ?

प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा : दिल्ली की सरकार को सारी बिजली नेशनल ग्रिड से मिलती है और वहां से बिजली काट दी जाती है। बदरपुर का प्लांट भी इसके पास है, अभी तक "डेसू" का अपना बोर्ड नहीं बना है, "डेसू" का बोर्ड बनाने की बात बहुत देर से चल रही है, पार्लियामेंट में घोषणा भी की गई है कि दिल्ली का अलग इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड बनाया जाएगा। ये सारी चीजें जब स्थगित पड़ी हुई हैं तो इन गर्मियों के अंदर बिजली की स्थिति कैसी रहेगी?

श्री अजीत जोगी : लगता है कि इनकी खुराना साहब से नहीं पटती ।

श्री कैलाश नारायण सारंग : तुम्हारी दिग्विजय सिंह से नहीं पट रही क्यों ?

SHRI P.V. RANGAYYA NAIDU: Sir, it is a fact that Delhi suffers from shortage of power and, natural, ly,-during summer months when the demand increases, DESU has to resort to certain load-shedding and also restriction on power supply to agriculture, and I think it is inevitable till such time we attain self-sufficiency; As regards the proposal for an Electricity Board, that is under consideration and a decision will be taken soon... *(Interruptions)*...

श्री ओम प्रकाश कोहली : सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि 1992-93 और 1993-94 का जो वर्ष चल रहा है, इसमें बिजली की कुल चोरी की कितना माता है, इसका कोई अनुमान इनके पास है या नहीं और बिजली की चोरी को रोकने के लिए प्रभावकारी कदम उठाने की दृष्टि कोई योजना है ? अगर है तो ऐसे कौन से कदम है ?

SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU: Sir, we do not have a figure for the its as such but. we have figures about. transmission .. and . distribution losses, which ate around 21.85 percent in 1992-93.

MR. CHAIRMAN: Well, it can wait now. The Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Expansion and motiernisation of *TV* and Radio Network

*223. SHRI VIRENDRA KATARIA: Will the Minister of INFORM)-ATIGNi AND BROADCASTING be pleased to stater

(a) how much subsidy was being given to the Ministry of information and Broadcasting for expanding and modernising TV and radio network;

(b) whether it is also a fact that a big chunk of subsidy has withdrawn when a lot of work is required to be done in this field; if so, the reasons therefor; and

(c) how this withdrawal has affected the expansion and modernisation programme of the Ministry?

THE MINISTER OF STATE OP THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI K. P. SINGH DEO): (a) No subsidy is being given to the Ministry of Information & Broadcasting for its Plan schemes 'for expansion and modernisation of TV and Radio Network. However, an outlay of Rs. 1134.95 Crores for All India Radio and Rs. 2300.00 Crores for Doordarshan has been approved for the VIII Five Year Plan. Against the total outlay of Rs. 3434.95 Crores, a budgetary support of Rs. 232.95 Crores is expected -to be provided by the Govern. ment for funding the Plan schemes of these media units.

(b) and (c) Whereas about 80 per cent of the Plan outlay was met through budgetary Support till the Seventh Plan only 20 per cent of the Plan outlay during the . Eighth Plan would be mot from this gourde. For the rest, funds will have to be found from extra budgetary sources. In view of this the various Plan. schemes of this Ministry, 'including those relating to the expansion and. modernisation of the electronic media are being repriorised.

Suspension of purchase of cotton by CCI

* 227. SHRI DILIP SINGH JUDEV:- Will the Minister of TEXTltES .....be.. pleased to state :

(a) whether it is it fact that the Cotton Corporation of India (CCI) has been. instritcted to suspend further purchase of cotton North lndia: